http://www.developindiagroup.co.in/

वार्षिक समसामयिक घटनाएं

2018-19

New Edition

समसामयिक घटनाओं से संबंधित यह किताब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। समसामयिकी से लगभग 70–80 प्रतिशत सवाल आप यहां पा सकते हैं।

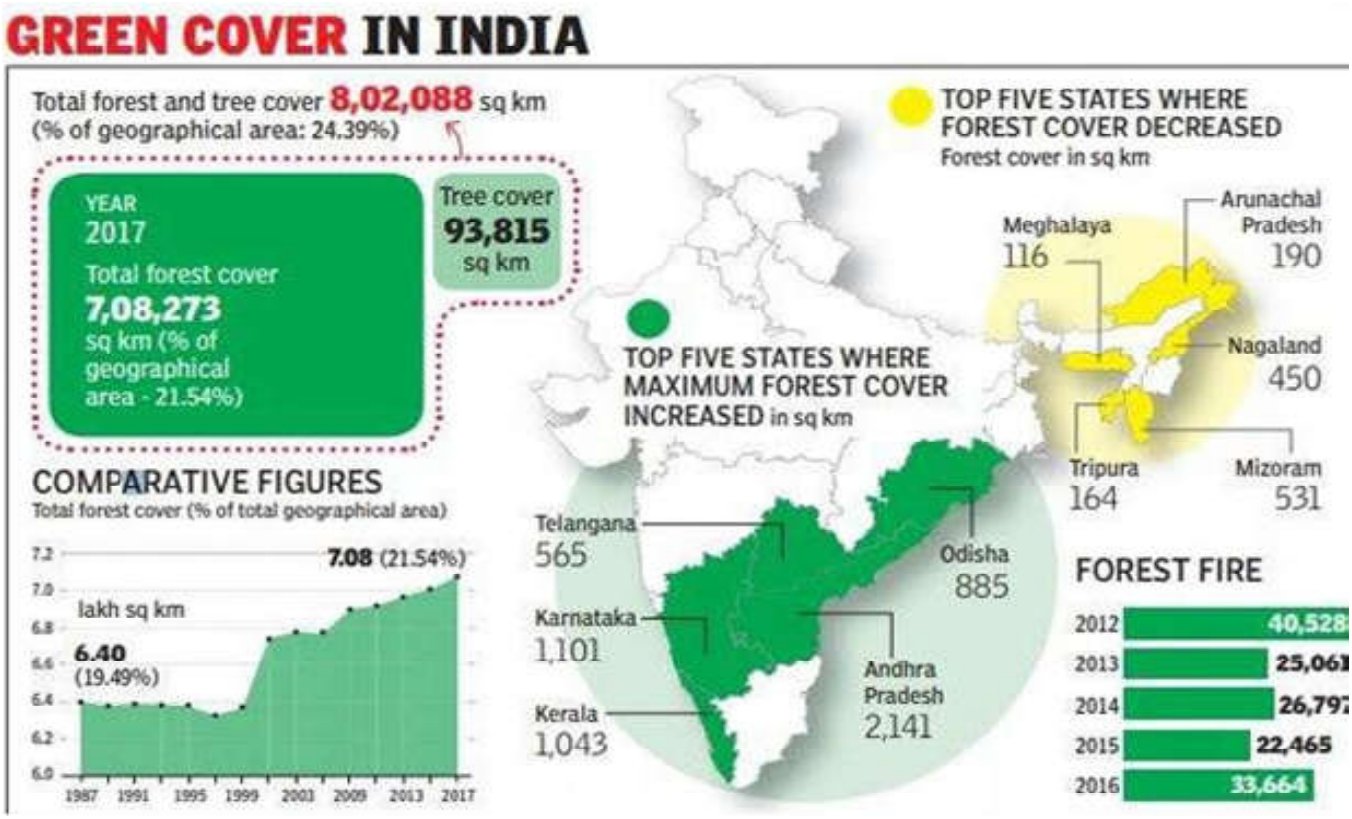

Published by
Develop India Group

PUBLISHED BY

Develop India Group

Allahabad (U.P.), India
Mobile : 08756987953
email : subscriptiondevelopindia@gmail.com
Website : https://developindiagroup.co.in/

Edition : 2018

Develop India Group Aims

We conduct Study Material Programme, All India Correspondence Courses, Test Series Programmes for various competitive exams. All things prepared by our expert faculties. Our aims to provide quality of comprehensive materials in a single place at your home according to your requirement.

Notes Prepared by

All study notes of DEVELOP INDIA GROUP prepared by our expert team and revised time to time. We have published these notes with carefully, but we can't take gaurantee for human as well as printing mistakes. If you want to give your feedback you can write us email : **subscriptiondevelopindia@gmail.com**

Terms & Conditions

If you want to buy any kind of study materials/previous year question papers, you can contact us.

Privacy Policy & Copywrite

All matter compile in this notes from various sources believed to be reliable. We published very carefully to this matter, its authors can not take guarantee the occuracy or completeness of any information published herein and neither Develop India Media Group nor its authors shall be responsible for any errors, omissions or damage arising out of use of this information.

No part of this notes may be reproduce or transemitted without the written permission of the publisher.

@ All right reserved. Refund is not available.

Note : All disputes will respect to this publication shall be subject to jurisdiction of the courts, tribunals and forums of Allahabad, India.

CORPORATE OFFICE

Develop India Media Group

Allahabad (U.P.); India
Mobile : 08756987953
emails : subscriptiondevelopindia@gmail.com,
developindiamediagroup@gmail.com
Website : https://developindiagroup.co.in/

अद्यतन समसामयिकी

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017

12 फरवरी, 2018 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ***भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017*** जारी किया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017, इस श्रृंखला की 15 वीं रिपोर्ट है। इसे देहरादून स्थिति भारतीय वन सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैंरू

- √ *भारत में कुल वन आवरण* **7,08,273 वर्ग किलोमीटर है जो कि** *देश के कुल वन क्षेत्र का 21.54 प्रतिशत* **है।**
- √ **देश के लगभग 40 प्रतिशत वन आवरण 10, 000 वर्ग किमी. या उससे अधिक आकार के 9 बड़े संस्पर्शी हिस्सों में मौजूद हैं।**
- √ *कुल वन और वृक्ष आच्छादनः* **देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आच्छादन 24.39 प्रतिशत है।**
- √ **रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल वन और पेड़ के आवरण में 8,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 2015 के मुकाबले एक प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।**
- √ **वन आवरण में वृद्धिः 2015 में पिछले मूल्यांकन की तुलना में, देश के कुल जंगल और वृक्ष कवर में 8021 वर्ग किमी (लगभग 80.20 मिलियन हेक्टेयर) की वृद्धि हुई है।**
- √ **वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि मुख्य रूप से अत्यंत घना वन (वीडीएफ) में वृद्धि के कारण और यह प्रसन्नता की बात है क्योंकि वीडीएफ ही वातावरण से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। वीडीएफ के पश्चात सर्वाधिक वृद्धि 'ऽुले वन' में हुई है।**
- √ **कुल वन क्षेत्र वृद्धि में वन 6,778 वर्ग किमी तथा वृक्ष आवरण 1,243 वर्ग किमी है।**
- √ **मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रः मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण 77,414 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (66,964 वर्ग किमी) और छत्तीसगढ़ (55,547 वर्ग किमी) का स्थान है।**
- √ **प्रतिशत वन क्षेत्र के मामले में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन आवरण लक्षद्वीप (90.33 प्रतिशत) में है। इसके बाद मिजोरम (86.27 प्रतिशत) और अंडमान निकोबार द्वीप (81.73 प्रतिशत) है।**
- √ **सफल कृषि वानिकी प्रथा, मैंग्रोव कवर, बेहतर संरक्षण और संरक्षण परंपराओं के कारण** *आंध्र प्रदेश, कर्नाटक* **और** *केरल* **में** *वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज* **की गई।**
- √ **आंध्र प्रदेश में 2141 वर्ग किमी., कर्नाटक में 1101 वर्ग किमी. और केरल में 1043 वर्ग किमी. की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है।**
- √ **15 राज्यों में 33 प्रतिशत से अधिक वन आवरणः देश के 15 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कुल क्षेत्रफल के मुकाबले वन क्षेत्र 33 प्रतिशत से ऊपर है।**
- √ **सात राज्यों – मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर में वन आवरण 75 प्रतिशत से अधिक है।**
- √ **आठ राज्यों – त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादरा एवं नागर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम में वन क्षेत्र 33 से 75 प्रतिशत के बीच है।**

तृतीय 'रायसीना' संवाद

छह दिन की भारत यात्रा पर आए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 16.01.2018 को जब भारत के महत्वाकांक्षी ***भू–राजनीतिक सम्मेलन 'रायसीना संवाद'*** के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया तो उन्होंने क्षेत्रीय और अंतराराष्ट्रीय राजनीति पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा वक्ता और 550 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन ताज पैलेस होटल में हुआ.

आतंकवाद का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इससे निपटने

Develop India Group

Why should read "Develop India Group" Study Material?

डेवेलप इंडिया ग्रुप अध्ययन सामग्री को क्यों पढ़ना चाहिए?

1. Develop India Group (DIG) is India's largest complete study materials provider website. डेवेलप इंडिया ग्रुप (DIG) भारत की सबसे बड़ी अध्ययन सामग्री प्रदाता वेबसाइट है।

2. Develop India Group (DIG) prepared their study materials in the guidance of highly qualified and experience mentoring specialist. डेवेलप इंडिया ग्रुप (DIG) ने सुयोग्य और अनुभवी सलाह विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी अध्ययन सामग्री तैयार की है।

3. Develop India Group (DIG) study materials have been prepared strictly according to revised syllabus. डेवेलप इंडिया ग्रुप (DIG) अध्ययन सामग्री पूर्णतया संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है।

4. Only aim behind preparing these study materials is to provide study material to those students, who are unable to attend coaching classes in mega cities. इन अध्ययन सामग्रियों को तैयार करने का उद्देश्य केवल उन छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करना है, जो महानगरों में कोचिंग क्लासेस में भाग लेने में असमर्थ हैं।

5. All kind of facts & data in this material have been collected from authentic sources. इस सामग्री में सभी प्रकार के तथ्यों और डेटा को प्रामाणिक स्रोतों से एकत्र किया गया है।

6. All kind of data is updated in quarterly in our study notes. हमारी अध्ययन सामग्रियों में सभी प्रकार के आंकडों को तिमाही में अपडेट किया जाता है।

7. Develop India Group (DIG) study materials have been prepared in simple language so that student can memorize easily and better understand. डेवेलप इंडिया ग्रुप (DIG) अध्ययन सामग्री सरल भाषा में तैयार की गई है ताकि छात्र आसानी से और बेहतर ढंग से समझ सके।

8. Complete syllabus of preliminary and main exam has been covered in this study material. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम इस अध्ययन सामग्री में शामिल किया गया है।

9. All important and relevant points have been highlighted in bold, underline and italic ways. बोल्ड, रेखांकन और इटैलिक तरीके से सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बिंदुओं को हाइलाइट किया गया है।

10. We have prepared our study materials with trained, talented, experienced team for each subject. They are supported by subject experts. हमने प्रत्येक विषय के लिए प्रशिक्षित, प्रतिभाशाली, अनुभवी टीम के साथ और विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अध्ययन सामग्री तैयार की है।

11. Once you will read these study materials, you will surely find 70 to 80 % questions in next coming examination. एक बार जब आप ये अध्ययन सामग्री पढ़ लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में 70 से 80: प्रश्न मिलेंगें।

12. So BUY TODAY and secure your future. इसलिए आज ही खरीदें और अपना भविष्य सुरक्षित करें.

Call us for more details : +91 8756987953

के लिए दुनिया की लोकतात्रिक ताकतों में साझेदारी जरुरी है। नेतन्याहू ने सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक और मूल्यों की ताकत का जिक्र किया और कहा कि मौजूदा हालात में सैनिक ताकत के साथ ही आर्थिक तौर पर मजबूत होना जरुरी है।

यह बहुपक्षीय सम्मेलन 2016 से सालाना दिल्ली में आयोजित हो रहा है। भारत के इस प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउन्डेशन संयुक्त रूप से करते हैं। ***इसे सिंगापुर की शंगरीला डायलॉग की तर्ज पर*** तैयार किया गया है।

मूडी ने बढ़ाई भारत की रेटिंग

भारत में आर्थिक सुधारों को लेकर बीते कुछ महीनों में बहस काफी तेज रही है और बहुत से आर्थिक जानकार भारत की स्थिति को बेहद खराब बता रहे हैं. हालांकि इसी बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग यानी साख बढ़ा दी है. पहले यह बीएए2 थी जिसे अब बढ़ा कर बीएए3 किया गया है. जनवरी 2004 के बाद यह पहला मौका है जब क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई गयी है. क्रेडिट रेटिंग का मतलब साख से है यानी इस देश को कर्ज देने या फिर निवेश करने वाली कंपनियों, सरकारों, संस्थाओं को अपना धन वापस मिलने की कितनी गारंटी है यह तय करने के लिए यह रेटिंग बनायी जाती है. इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, आर्थिक सुधारों और कुछ दूसरे आर्थिक मानकों को आधार बनाया जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मजबूत अर्थव्यवस्था और युवाओं की बढ़ती आबादी को रोजगार देने के वादे पर चुनाव जीता था. हालांकि बीते महीनों में आर्थिक जानकार लगातार देश की अर्थव्यवस्था के बुरे हाल में होने की बात कह रहे हैं. यहां तक कि बीजेपी के अंदर से भी कई नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठायी है. मूडी की नई रेटिंग आने के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि यह अपग्रेड, ष्बीते कुछ सालों में भारत में उठाये सकारात्मक कदमों की देर से की गयी पहचान है. यह काफी उत्साह बढाघ्ने वाला है कि हमारे कदमों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. साथ ही जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर बने रहने के हमारे निश्चय को भी मजबूत करेगा.ष अरूण जेटली ने यह भी कहा कि जो लोग भारत में सुधार प्रक्रिया पर संदेह जता रहे थे वो भी अपने रुख पर दोबारा विचार करेंगे.

मूडी का कहना है कि हाल में किए गये सुधारों से आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी, विदेशी और घरेलू निवेश में तेजी आएगी, साथ ही ष्मजबूत और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा.ष इन सुधारों में राष्ट्रीय स्तर पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और टैक्स चोरी को रोकने के लिए 2016 के विवादित नोटबंदी को भी शामिल किया गया है. भारत के बारे में मूडी ने कहा है, ष्अर्थव्यवस्था में लगातार विकास और संस्थागत सुधार समय के साथ भारत की उच्च विकास क्षमता को बढ़ायेंगे.ष्मूडी और स्टैडर्ड एंड पूअर्स ने दो महीने पहले कर्ज के बढ़ते बोझ का हवाला दे कर चीन की क्रेडिट रेटिंग घटाई थी.

सौभाग्य योजना

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब सिर्फ 3000 से भी कम गांव ऐसे बचे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है. लेकिन, सरकार भी मानती है कि देश में चार करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है और वह अंधेरे में जीने को मजबूर हैं. 25. 09.2017 को यह ऐलान किया कि अब वह इस स्थिति को बदलने जा रही है. *प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती के मौके पर सौभाग्य नाम की योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद है हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना.*

इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह खुद मिट्टी तेल के दीए में पढ़ चुके हैं और इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची है वहां जिंदगी कितनी मुश्किल होती है. उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना से 2018 दिसंबर तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश में कोई भी घर अंधेरे में ना रहे. यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इसे एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहेगी.

सौभाग्य योजना के लिए सरकार ने 16,320 करोड़ रुपये का बजट रखा है और हर घर तक बिजली पहुंचाने का 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठाएगी 10 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारों को उठाना होगा और 30 प्रतिशत बैंकों से लोन लिया जाएगा. इस योजना की खास बात यह है कि लोगों को अपने घर में बिजली कनेक्शन पाने के लिए कोई खर्च नहीं करना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद बिजली का कनेक्शन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने का सिलसिला भी बंद हो जाएगा. क्योंकि सरकार खुद लोगों के घर–घर जाकर बिजली कनेक्शन लगाएगी और उन लोगों की पहचान करेगी जिनके घर बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं है.

प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप का सहारा लिया जाएगा और लोग बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन देने से लेकर सारी कार्यवाही मोबाइल के जरिए ही पूरी कर सकेंगे. गरीब लोगों के लिए बिजली कनेक्शन पाने की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त होगी. लेकिन बाकी

लोगों को भी इसके लिए सिर्फ 500 खर्च करने होंगे और वह भी 10 किश्तों में बिजली बिल के साथ लिया जाएगा.

देश के दूरदराज इलाकों में जहां हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाना मुश्किल है वहां सरकार घरों को रोशन करने के लिए सौर ऊर्जा का सहारा लेगी और लोगों को बैटरी, 5 LED लाइट और एक पंखा भी दिया जाएगा.

सौभाग्य योजना से पहले *मोदी सरकार ने हर घर तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई थी जिसके तहत अब तक तीन करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन बांटे जा चुके हैं.* उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के चुनाव में BJP को उज्वला योजना का जबरदस्त फायदा मिला.

ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 103वीं रैंक

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक) में 130 देशों की लिस्ट में भारत 103वें स्थान पर है। ये रैंक ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका) में भी सबसे नीचे है। नॉर्वे इस लिस्ट में टॉप पर है। ये इंडेक्स इस बात का संकेत होता है कि कौन–सा देश अपने लोगों के डेवलपमेंट, उनकी टीचिंग– ट्रेनिंग और टैलेंट के इस्तेमाल में कितना आगे है।

इस बार की लिस्ट में नॉर्वे ने टॉप पर जगह बनाई है और इस देश ने पिछले बार के टॉप पर बरकरार फिनलैंड को इस बार दूसरे स्थान पर धकेल दिया है।

जेनेवा के डब्ल्यूईएफ (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इम्प्लॉयमेंट में जेंडर गैप के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे पीछे है। हालांकि फ्यूचर के लिए जरूरी स्किल्स के डेवलपमेंट के मामले में भारत की स्थिति बेहतर है और इस मामले में 130 देशों के बीच इसकी रैंक 65 है। फोरम ने पिछले साल की अपनी रिपोर्ट में भारत को 105वीं रैंक दी थी और कहा था कि यह देश अपनी ह्यूमन कैपिटल की संभावनाओं का सिर्फ 57 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर पा रहा है। उस लिस्ट में फिनलैंड टॉप पर था। WEF की लिस्ट किसी देश के लोगों की नॉलेज और स्किल के आधार पर तैयार होती है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में उस देश की वैल्यू को बताती है और उसकी ह्यूमन कैपिटल रैंक तय करती है।

WEF के मुताबिक इस साल की लिस्ट में ब्रिक्स देशों में रूस सबसे आगे है। उसे 16वीं रैंक मिली है। चीन को 34वीं, ब्राजील को 77वीं और साउथ अफ्रीका को 87वीं रैंक हासिल हुई है। नई लिस्ट में शामिल साउथ एशिया के देशों में भारत, श्रीलंका और नेपाल से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आगे है। **ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत के पीछे रह जाने की रिपोर्ट में कई वजहें बताई गई** हैं। मसलन– *एजुकेशन की फील्ड में पिछड़ना* और *ह्यूमन कैपिटल का कम फैलाव होना*। WEF के मुताबिक इसका मतलब है कि *भारत में अवलेबल स्किल का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा* है।

ब्रिक्स का शायमेन डिक्लेरेशन

ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। चीन चाहता था कि भारत इस मंच पर पाक के खिलाफ आतंकवाद का मुद्दा न उठाए, लेकिन ब्रिक्स देशों की ओर से जो घोषणापत्र का मजमून सामने आया है, उसमें आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है। और तो और, पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन की भी कड़ी निंदा की गई है। यह घोषणापत्र अहम है क्योंकि चीन कई बार जैश–ए–मोहम्मद चीफ मसूद अजहर पर यूएन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की दिशा में अड़ंगा लगा चुका है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को साथ जोड़ने में कामयाब हो गया है।

शायमेन डिक्लेरेशन में लिखा है, श्हम ब्रिक्स देशों समेत पूरी दुनिया में हुए आतंकी हमलों की निंदा करते हैं। हम सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं, चाहे वो कहीं भी घटित हुए हों और उसे किसी ने अंजाम दिया हो। इनके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। हम क्षेत्र में सुरक्षा के हालात और तालिबान, आईएसआईएस, अलकायदा और उसके सहयोगी, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर–ए–तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान और हिज्ब–उत–ताहिर द्वारा फैलाई हिंसा की निंदा करते हैं।श

घोषणापत्र में लिखा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। यह काम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक होना चाहिए। इसमें देशों की संप्रभुता का खयाल रखना चाहिए, अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम एक साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ व्यापक संधि को स्वीकार किए जाने के काम में तेजी लाई जानी चाहिए। कट्टरपंथ रोके जाने का प्रयास होना चाहिए।

ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने सभी देशों से अपील की कि वे आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र रूख अपनाए। आतंकवाद से निपटने के क्रम में चरमपंथ से निपटने और आतंकियों के

वित्त पोषण के स्रोतों को अवरूद्ध करने की भी बात की गई। समूह ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति के साथ–साथ तालिबान, आईएसआईएस, अल–कायदा और लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद एवं हक्कानी नेटवर्क समेत इसके सहयोगी संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसा पर चिंता जाहिर की। समूह ने ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, तहरीक–ए–तालिबान और हिज्ब उत–तहरीर जैसे आतंकी संगठनों का भी जिक्र किया।

ब्रिक्स ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से कंप्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेरेरिज्म अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र समझौते को जल्दी ही अंतिम रूप दिए जाने और इसे अंगीकार किए जाने की मांग करते हैं।

भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के शहर श्यामेन में हैं। पीएम ने ब्रिक्स बैठक में बोलते हुए कहा कि सभी देशों में शांति के लिए ब्रिक्स देशों का एकजुट रहना जरूरी है। उन्होंने सम्मेलन में आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया। इस पर अन्य सदस्य देशों ने भी चिंता जताई। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया।

बता दें कि ये ब्रिक्स का 9वां सम्मेलन है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को आगे ले जाने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत भागीदारी का आज आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक ने सहयोग के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित किया है और अनिश्चितता की तरफ बढ़ रही दुनिया में स्थिरता के लिए योगदान दिया है। मोदी ने आंतकवाद का भी मुद्दा उठाया। इस पर ब्रिक्स देशों ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और तालिबान, अल–कायदा, पाकिस्तान आधारित लश्कर–ए–तैयबा एवं जैश–ए–मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों द्वारा की जा रही हिंसा पर चिंता जतायी।

चीन के शियामन शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि व्यापार और अर्थव्यवस्था ब्रिक्स–ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग का आधार हैं। उन्होंने विकासशील देशों की संप्रभु और कॉरपोरेट कंपनियों की वित्तीय आवयश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी बनाए जाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवोन्मेष और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सदस्य देशों के बीच मजबूत भागीदारी विकास को आगे ले जाने, पारदर्शिता को बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने में मदद कर सकती है। उन्होंने सदस्य देशों के सेंट्रल बैंकों से अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने और समूह तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आकस्मिक विदेशी मुद्रा कोष व्यवस्था के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। मोदी ने स्मार्ट शहरों, नगरीकरण और आपदा प्रबंधन में सहयोग की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने सहयोग, स्थिरता में योगदान तथा अनिश्चितता की दिशा में बढ़ रही दुनिया में विकास के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित किया है। हमारे प्रयास आज कृषि, संस्कृति, पर्यावरण, ऊर्जा, खेल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं। मोदी ने कहा कि गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, ऊर्जा तथा शिक्षा सुनश्चित करने के लिए समूह मिशन मोड में है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम हैं जो महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में लाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास के लिए सभी करें काम– जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि जिस तरह से दुनिया में परिवर्तन हुए हैं, उसके बाद ब्रिक्स में देशों का सहयोग अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमारे मतभेदों के बावजूद हमारे 5 देश डीजीएचपीएनएटी के समान चरण में हैं और समान विकास साझा करते हैं। हमें एक आवाज से बात करनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं विकास से संबंधित मुद्दों के लिए संयुक्त रूप से समाधान पेश करना चाहिए। चीन ने एनडीबी परियोजना तैयार करने के लिए 4 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है ताकि बैंक का संचालन और और उसका विकसा लंबे समय तक किया जा सके। शी ने कहा कि दुनिया के अन्य भागों से भी हमें अपने संबंध मधुर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के हम 5 देश वैश्विक शासन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारे सहयोग के बिना दुनिया की चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता।

ओडिशा ने व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया

देश के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक के रूप में ख्याति प्राप्त डॉ. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि (27.07.2017) पर उन्हें देशभर में याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई. पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि पर ओडिशा सरकार ने भद्रक जिले में बाहरी ***व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा*** है.

राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री महेश्वर मोहंती ने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद कल गजट अधिसूचना जारी की. मोहंती ने गजट अधि

ासूचना की एक प्रति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सौंपी , जिन्होंने पूर्व में व्हीलर द्वीप का नाम कलाम के नाम पर करने की घोषणा की है.

पटनायक ने पूर्व राष्ट्रपति की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि दीं. समारोह में उन्होंने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप और बालेश्वर जिले में चांदीपुर के अस्थायी प्रक्षेपण स्थल से कलाम के भावनात्मक जुड़ाव को याद किया. श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाम ने देश की प्रतिरक्षा के लिए मिसाइल विकसित करने के अपने प्रयासों के तहत इन दो जगहों पर सबसे अधिक समय बिताया हैं.

कोंकणी साहित्यकार महाबलेश्वर सैल को 'सरस्वती सम्मान'

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान अगले हफ्ते कोंकणी साहित्यकार महाबलेश्वर सैल को दिया जाएगा.

के के बिरला फाउंडेशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि वर्ष 2016 का 'सरस्वती सम्मान' आगामी 30 अगस्त को यहां राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा सैल को उनके उपन्यास 'होथन' के लिए दिया जाएगा.

74 वर्षीय लेखक ने चार मराठी नाटक और सात कोंकणी उपन्यास लिखे हैं. इसके अलावा उन्होंने मराठी भाषा में पांच लघु कथाएं और एक उपन्यास भी लिखा है. फाउंडेशन के लिए इस पुरस्कार में 15 लाख रुपये का नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया था.

सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में अब पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार करने के फरमान को दंडनीय अपराध बनाया गया है और ऐसे मामलों में दोषी को सात साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इस तरह का कानून बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार रोकथाम अधिनियम, 2015 को पिछले महीने मंजूरी दी और इसे तीन जुलाई को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

कानून के तहत सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी करने वाले जाति और समुदाय परिषद जैसे अर्द्धन्यायिक इकाइयों के सदस्यों को सात साल तक की कैद या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य विधानसभा ने 13 अप्रैल, 2016 को विधेयक को पारित किया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा था।

सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में नागरिक के निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। इसके साथ ही निजता अब मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज केएस पुट्टस्वामी ने सन् 2012 में श्आधारश् को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले समेत 21 पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने फैसला देते हुए कहा है कि प्राइवेसी या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है.

संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकार के प्रावधान हैं, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था. अनुच्छेद–21 में जीवन तथा स्वतन्त्रता का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में निर्णय देकर शिक्षा, स्वास्थ्य, जल्द न्याय, अच्छे पर्यावरण आदि को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है. संविधान के अनुच्छेद–141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून माना जाता है, और अब प्राइवेसी भी मौलिक अधिकार का हिस्सा बन गई है. मौलिक अधिकार होने के बाद कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करके न्याय की मांग कर सकता है.

सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया कि प्राइवेसी कॉमन लॉ के तहत कानून तो है पर इसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता. इस बारे में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पुराने दो फैसलों खड़क सिंह (1954) और एमपी शर्मा (1962) की जोरदार दलील दी गई थी. पिटीशनर्स के अनुसार संविधान में जनता सर्वोपरि है तो फिर प्राइवेसी को मौलिक अधिकार क्यों नहीं माना जाना चाहिए? पिटीशंस ने अमेरिका में प्राइवेसी के बारे में चौथे अमेंडमेंट समेत कई अन्य दलीलें रखीं. सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर्स की तरफ से पेश दलीलों को मानते हुए प्राइवेसी को मौलिक अधिकार मान लिया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले लगाई रोक के बावजूद सरकार द्वारा श्आधारश् को 92 कल्याणकारी योजनाओं में अनिवार्य बना दिया गया था. श्आधारश्

ाारश के तहत लोगों को निजी सूचनाओं के साथ बायोमैट्रिक्स यानि फेस डिटेल्स, अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के निशान देने पड़ते हैं. श्आधारश को इनकम टैक्स समेत कई अन्य जगहों पर जरूरी कर दिया गया है. श्आधारश की अनिवार्यता और बायोमैट्रिक्स के सरकारी डेटाबेस को प्राइवेसी के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी. इस मामले में पहले तीन जजों की बेंच में और फिर पांच जजों की बेंच ने सुनवाई की. खड़कसिंह मामले में 8 जजों की बेंच ने फैसला दिया था इसलिए प्राइवेसी के मामले पर फैसले के लिए नौ जजों की बेंच बनाई गई. संविधान पीठ के इस फैसले के बाद अब पांच जजों की बेंच श्आधारश मामले पर सुनवाई करेगी.

आधार के अलावा सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पालिसी को चुनौती दी गई थी. प्राइवेसी पर संविधान पीठ के फैसले के बाद व्हाट्सऐप मामले पर पांच जजों की बेंच सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जस्टिस चन्द्रचूड़ ने डिजिटल कम्पनियों द्वारा डेटा कलेक्शन पर चिंता जताई थी. फैसले में जस्टिस सप्रे ने डिजिटल कम्पनियों द्वारा डेटा ट्रान्सफर और प्राइवेसी के उल्लघंन पर चिंता जताई. फैसले में लिखा गया है कि उबर कम्पनी बगैर टैक्सी के, फेसबुक बगैर कंटेन्ट के और अलीबाबा बगैर सामान के ही विश्व की बड़ी कम्पनी बन गई हैं. केएन गोविन्दाचार्य ने सन् 2012 में दिल्ली हाईकोर्ट में डिजिटल कम्पनियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए इन कम्पनियों के ऑफिस और सर्वर्स भारत में स्थापित करने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेसी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने पूर्व जज श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा प्रोटेक्शन पर कघनून बनाने के लिए समिति का गठन कर दिया था. तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी दिन से लागू हो गया. प्राइवेसी पर नौ जजों ने सहमति से ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसे तुरंत प्रभाव से सरकार को लागू करना पड़ेगा. इस फैसले के बाद सरकार को इंटरनेट और मोबाइल कम्पनी द्वारा डेटा के गैर–कघनूनी कारोबार पर रोक लगानी होगी, जिससे डिजिटल इंडिया के विस्तार पर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं.

फैसले के बाद सरकार के सामने चुनौतियाँ

इस फैसले के बाद सरकार को आधार कानून में बदलाव करने के साथ डेटा प्रोटेक्शन पर जल्द ही कघनून बनाना होगा. डिजिटल इंडिया के व्यापक दौर में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अपनी भूमिका के निर्वहन में विफल रही है. प्राइवेसी के कघनून को लागू करने के लिए सरकार को प्रभावी रेगुलेटरी व्यवस्था बनाना होगा. इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पिटीशन्स और पीआईएल का दौर आया तो अदालतों में मुकदमों का बोझ और बढ़ जायेगा.

क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है ?

शाहबानो मामले में राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था. राज्यसभा में बहुमत नहीं होने से सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शायद ही बदल पाए. 1973 में केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव करने के लिए संसद कघनून नहीं बना सकती. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को अक्टूबर–2015 में निरस्त कर दिया था. प्राइवेसी अब मौलिक अधिकार है जिसे संसद के कघनून द्वारा अब बदलना मुश्किल है.

सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि विकासशील देश में जनता की भलाई के लिए कुछ अभिजात्य लोगों की प्राइवेसी को देशहित में दर–किनार किया जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश के सभी 127 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना में खाता खुलवाने की आयु सीमा बढ़कर 65 साल हो गई

राष्ट्रीय पेंशन योजना में खाता खुलवाने की आयु सीमा बढ़कर 65 साल हो गई है। पेंशन क्षेत्र के नियामक पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इसकी घोषणा की। पीएफआरडीए के अध्यक्ष हेमंत कांट्रेक्टर ने बताया कि एनपीएस से जुड़ने की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 18– 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय हो गया है। इस बारे में पीएफआरडीए बोर्ड ने फैसला ले लिया है और जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना में आयु सीमा बढ़ाए जाने का विकल्प है और आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष तक करने की योजना है। पेंशन में रिफॉर्म करने के सरकार के निर्णय के पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पोर्टेबिलिटी को बढ़ाना या एनपीएस में वृद्धावस्था फंड को स्थांतरित कर इसे ज्यादा आकर्षक और ग्राहकों के लिए आसान बनाना है।

कांट्रेक्टर ने कहा कि उनका उद्देश्य ऐसे सेक्टर के लिए पेंशन योजना शुरू करना है जहां यह उपलब्ध नहीं है। इस समय देश में सिर्फ 15 से 16 फीसदी कामगारों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत में लगभग 85 फीसदी कामगार असंगठित और अनियमित क्षेत्रों में काम करते हैं।

देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 09.09.2017 को देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का भूमि पूजन किया। लगभग 7000 करोड़ रुपये की यह परियोजना दो वर्षों में मूर्त रूप लेगी। उपराष्ट्रपति ने इसके साथ ही स्मार्ट सिटी परिसर में प्रस्तावित 690 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत वाले अर्बन सिविक टावर, कंवेंशन सेंटर तथा झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (जुपमी) के बिल्डिंग निर्माण की आधारशिला भी रखी।

इस बीच उन्होंने जहां झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जुटकोल), रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट की लांचिंग की, वहीं स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान का विमोचन भी किया।

रांची स्थिति एचईसी के कोर कैपिटल एरिया में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के भूमि पूजन समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट सिटी की स्मार्ट परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए स्मार्ट लीडर की जरूरत है। ऐसा लीडर जिसमें क्षमता हो, दूरदर्शिता हो, स्पष्टवादिता हो, जनता के प्रति कमिटमेंट हो। हाई–फाई, कोट–टाई, सूट–बूट नहीं चलेगा।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि कि दुनिया आगे बढ़ रही है। फिर हम पीछे क्यों रहें? बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, 24 घंटे बिजली, जलापूर्ति, अच्छी सड़कें, सीवरेज, पार्क, आईटी कनेक्टिविटी, नो व्हीकल जोन, स्मार्ट मीटरिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, पैदल पथ आदि स्मार्ट सिटी की पहचान हैं।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2017 घोषित

खेलो में उत्कृष्टता को पहचानने और खिलाडियों को पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता बनाने के लिए प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल विकास में जीवन–भर योगदान के लिए ध्यान चंद पुरस्कार दिया जाता है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की. पैरा एथलीट देवेंद्र और हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

29 अगस्त 2017 को राष्ट्रपति भवन में विशेष आयोजन समारोह में पुरस्कार विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया.

राजीव गांधी खेल रत्न 2017

1.श्री देवेन्द्र	पैरा एथलीट
2. श्री सरदार सिंह	हॉकी

द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017

1. स्वर्गीय डॉ आर गांधी	एथलेटिक्स
2. श्री हीरा नंद कटारिया	कबड्डी
3. श्री जी एस एस वी प्रसाद	बैडमिंटन (स्पमि. जपउम)
4. श्री बृज भूषण मोहंती	मुक्केबाजी (स्पमिजपउम)
5. श्री पी.ए. राफेल	हॉकी (स्पमिजपउम)
6. श्री संजय चक्रवर्ती	शूटिंग (स्पमिजपउम)
7. श्री रोशन लाल	कुश्ती (स्पमिजपउम)

क्या है रैंजमवेयर साइबर अटैक ?

रैंजमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर वाइरस है जिसको हैकर्स के द्वारा आपके डेस्कटॉप में किसी ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजा जाता है. इस वायरस में इतना पॉवर होती है कि यह आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को लॉक कर देता है. आप इसके बाद यूजर चाह कर भी इसे अनलॉक नहीं कर पायेगे. लॉक होने के स्थिति में आप अपने सिस्टम को हैकर्स को पैसे पेय करने के बाद भी अनलॉक कर पायेगे या नहीं इस बात पर संदेह है. इस तरीके का यूज कर हैकर लोगो से पैसे निकलवा लेते है. वैसे रैंजमवेयर वायरस का सबसे ज्यादा अटैक विंडोज क्ष्क्र पर देखा गया है. मास्को की कंपनी के जारी किये गए अपडेट पर ध्यान दे तो यह वायरस 2,18,624 रैंजमवेयर फिलो की पहचान की गयी है.

चेनानी–नाशरी सुरंग

चेनानी–नाशरी सुरंग जिसे पत्नीटॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पुनः निर्धारण से पूर्व नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए) पर स्थित एक सड़क सुरंग है। इसका कार्य वर्ष 2011 में आरम्भ हुआ तथा उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया।

यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 कि. मी. (5.8 मील) है। सुरंग बनाने पर मूल अनुमानित लागत 2,520 करोड़ (यूएस + 367.92 मिलियन) थी लेकिन परिवर्धित करने में कुल 3,720 करोड़ (यूएस + 543.12 मिलियन) खर्च हुये। मुख्य सुरंग का व्यास 13 मीटर है, जबकि समानांतर निकासी सुरंग का व्यास 6 मीटर है। मुख्य और निकासी सुरंगों में 29 स्थानों पर पार मार्ग बनाये गये हैं जो हर 300 मीटर की दूरी पर स्थिति हैं। यह देश की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत सुरंग प्रणाली वाली सुरंग है।

सुरंग की सहायता से जम्मू और श्रीनगर के मध्य दूरी 30.11 कि.

Develop India Group

मी. (18.7 मील) रह गयी और यात्रा समय में दो घण्टे की कटौती हो गयी। पत्नीटॉप पर सर्दियों में बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बाधा उत्पन्न होती थी तथा प्रत्येक शीतकाल में कई बार वाहनों की लम्बी कतार के कारण भी बाधा उत्पन्न होती थी – कई बार कई दिनों तक कतार में रहना पड़ता था। सुरंग पत्नीटॉप, कुद और बटोत को उपमार्गों से जोड़ती है जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सर्दियों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया है।

1. **सुरंग निचले हिमालय परास में स्थिति है जिसकी ऊँचाई 1200 मीटर है।**
2. **चेनानी–नाशरी सुरंग को आस्ट्रिया की नई सुरंग प्रौद्योगिकी से बनाया गया है। इसमें सुरक्षा के कई प्रावधान हैं। सभी का संचालन एक सॉफ्टवेयर से होता है।**
3. **इस परियोजना को बनाने का टेंडर एनएचआई के साथ आईएल एंड एफएस को मिला था।**
4. **यह सुरंग जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग को चार लेन का करने की परियोजना का हिस्सा है। जम्मू–श्रीनगर के बीच यात्रा की अवधि घटाने के लिए बारह ऐसी ही और सुरंग परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है।**
5. **यह सुरंग ऊधमपुर जिले के चेनानी और रामबन जिले के नाशरी के बीच की 41 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 10.89 किलोमीटर कर देगी और यह फासला महज दस मिनट में पार कर लिया जाएगा। अभी इसमें ढाई घंटे लगते हैं।**
6. **जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग को राज्य की जीवन रेखा माना जाता है।**
7. **सभी 12 सुरंगों का निर्माण पूरा होने के बाद जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की 293 किलोमीटर की दूरी में से 62 किलोमीटर घट जाएंगे। यह 231 किलोमीटर की दूरी चार–साढ़े चार घंटे में तय कर ली जाएगी।**
8. **इस सुरंग की बेहद खास बात हर 150 मीटर पर एक आपातकालीन एसओएस कॉल बॉक्स और बाहर निकलने के लिए बचाव के रास्ते का होना है। इस रास्ते से होकर मुसाफिर सुरक्षा सुरंग तक जा सकेंगे जो इस मुख्य सुरंग के समानांतर बनाई गई है।**
9. **राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने फैसला किया है कि जम्मू एवं कश्मीर में लेह और श्रीनगर के बीच बनने वाली 14 किलोमीटर लंबी जोजी ला सुरंग को इसी तकनीक से बनाया जाएगा।**

जीबीयू–43

अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा बम गिराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. अमेरिका ने जो बम जीबीयू–43 अफगानिस्तान पर गिराया है, वो इतना खतरनाक है कि उसके सवा तीन किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खाक हो जाएगा. इस बम को नानगरहार प्रांत के अचिन जिले में एक सुरंगनुमा इमारत पर गिराया गया है. अफगानिस्तान में अमेरिकी सुरक्षा बलों ने एक बयान में यह जानकारी दी. ये हमला वहां के समय के मुताबिक शाम 7.32 बजे हुआ. ये हमला भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले की तरह ही अमेरिकी सरकार के द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला है. अगस्त 6 और अगस्त 9, 1945 को हुए इस हमले में 2 लाख 46 के करीब लोग मारे गए थे. अमेरिकी वायु सेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम ष्लिटिल बॉय गिराया था. उसके तीन दिनों बाद अमरीका ने फिर नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया. हालांकि जीबीयू–43 परमाणु बमों की श्रेणी में नहीं आता है.

अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि उसने पूर्वी अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के ठिकानों पर सबसे बड़ा और खतरनाक जीबीयू–43 बम गिराया है. इस बम को सबसे शक्तिशाली बम बताया जाता है. पेंटागन के प्रवक्ता ने बताया कि पहली बार इस बम का प्रयोग किया गया है और इसे छ–130 एयरक्राफ्ट से गिराया गया.

21600 पौंड वजनी (तकरीबन 10 हजार किलो) इस बम का नाम जीबीयू–43 है. इसे मदर ऑफ आल बम भी कहा जाता है. इस तरह का बम पूरी दुनिया में सिर्फ 15 है. सवा तीन किलोमीटर के दायरे में यह सब कुछ खाक कर देता है. यह बम जीपीएस से संचालित होता है. ऐसे में इसके निशाना चूकने का कोई सवाल ही नहीं. जीबीयू–43 बम से 11 टन TNT के बराबर धमाका होता है. इस बम को बनाने में तकरीबन दो हजार करोड़ रुपये का खर्च आता है.

वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2017

यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2017 में नॉर्वे को दुनिया का सबसे खुशी देश करार दिया गया है। यह पिछले साल चौथी रैंक पर था। इस बार यह डेनमार्क को पीछे छोड़ नंबर वन बन गया है। वहीं, 155 देशों की लिस्ट में चीन 79वें, पाकिस्तान 80वें और भारत 122वें नंबर पर है। यानी यूएन यह मानता है कि भारतीयों से ज्यादा पाकिस्तानी खुश

रहते हैं। बता दें कि पिछली बार भारत इस लिस्ट में 118वें नंबर पर था। इस बार वह रैंक में चार पायदान और पीछे हो गया है।

वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2017 तैयार करने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के डायरेक्टर जैफरी एस. ने कहा कि खुश देश वो हैं जहां खुशहाली, सोसायटी में आपसी भरोसा, लोगों के बीच बराबरी और सरकार पर भरोसा ज्यादा है और इन सभी के बीच अच्छा बैलेंस है।

इस सालाना रिपोर्ट का मकसद सरकारों और सिविल सोसायटी को खुशहाली के बेहतर तरीके बताना हैं।देशों के हैप्पीनेस इंडेक्स को वहां प्रति व्यक्ति जीडीपी, अच्छी लाइफ एक्सपेंटेंसी, फ्रीडम, सोशल सपोर्ट, उदारता और सरकार या बिजनेस में जीरो करप्शन के पैमाने पर आंका गया।

टॉप–10 में शामिल देश

1 नॉर्वे
2 डेनमार्क
3 आईसलैंड
4 स्विट्जरलैंड
5 फिनलैंड
6 नीदरलैंड
7 कैनेडा
8 न्यूजीलैंड
9 ऑस्ट्रेलिया
10 स्वीडन
79 चीन
80 पाकिस्तान
122 भारत

2012 से हर साल आ रही इस रिपोर्ट में 2016 में डेनमार्क नंबर वन और नॉर्वे नंबर 4 पर था। इस बार वह नंबर–1 हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्वे ने अपने देश में तेल की कम कीमतों के बावजूद नंबर–1 रैंक हासिल की है। यह देश सिर्फ ऑयल वैल्थ के चलते सबसे ज्यादा हैप्पी नहीं है। वह ऑयल को काफी धीरे–धीरे प्रोड्यूस कर रहा है। मौजूदा दौर की बजाय फ्यूचर की चीजों पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है।

नॉर्वे में लोगों के बीच आपसी भरोसे का भाव है। ज्यादातर लोग एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। वहां के लोगों में उदारता है। देश में गुड गवर्नेंस है। सब–सहारा अफ्रीका में आने वाले देश जैसे सीरिया और यमन 155 देशों की लिस्ट में सबसे कम खुश हैं। हैप्पीनेस के 6 पैमानों पर ये देश सबसे कमजोर हैं।

मेधा

आजादी के करीब 70 साल बाद भारत की पहली मेड इन इंडिया ट्रेन 18.03.2017 से चलनी शुरू. रेलमंत्री सुरेश प्रभु मुंबई में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. भारत की स्वदेशी ट्रेन का नाम श्मेधाश रखा गया है. अपनी पहली यात्रा में मेधा ट्रेन ने मुंबई के चर्चगेट से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) तक की यात्रा की.

इससे पहले श्मेधाश ट्रेन का कई चरण में सफल ट्रायल किया जा चुका है. इस ट्रेन को कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी (सीआरएस) की स्वीकृति मिल चुकी है.

भारत की स्वदेशी ट्रेन में कई ऐसी खूबियां हैं जो उसे दुनिया के कई ट्रेनों से उसे अगल बनाती है. इस ट्रेन में एक साथ 6,050 यात्री यात्रा कर सकते हैं. इसमें 1,168 सीटे हैं. इस ट्रेन की स्पीड 110 किमी प्रति घंटा है.

इस ट्रेन में फ्रेश एयर कूलिंग क्षमता 16,000 प्रति घंटा मीटर क्यूबिक है. रिजेनरेटड ब्रेकिंग सिस्टम युक्त यह रेक 30 से 35 प्रतिशत बिजली परिचालन के दौरान बचा सकती है. रेलवे अधिकारी के मुताबिक मेड–इन–इंडिया ट्रेन श्मेधाश को बनाने में लगभग 43.23 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. जबकि विदेश से खरीदी जाने वाली बॉम्बार्डियर ट्रेन की कीमत 44.36 करोड़ रुपए है.

मेक इन इंडिया के तहत देश की पहली स्वदेशी लोकल श्मेधाश हैदराबाद मेधा सर्वो ड्राइव्स फर्म की ओर से प्रायोजित है और चेन्नई कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है. वर्तमान में मध्य और पश्चिम रेल पर परिचालित होने वाली लोकल चौन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में तैयार होती है. इन लोकल ट्रेनों में इलेक्ट्रिक तकनीकी समेत अन्य तकनीकी संबंधी काम सीमेंस और बॉम्बार्डियर कंपनियों की देख रेख में होता है. ये कंपनियां विदेशी है.

ब्रिटेन की संसद ने पारित किया ब्रेग्जिट विधेयक

ब्रिटेन की संसद ने 'ब्रेग्जिट विधेयक' पारित करते हुए प्रधानमंत्री टेरीजा मे के लिए यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी पर बातचीत शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने 13.03.2017 को हाउस ऑफ लॉर्डस के संशोधनों को 335–287 मतों के अंतर से खारिज कर दिया था। इन संशोधनों में सरकार से कहा गया था कि वह ब्रेग्जिट वार्ताओं की शुरूआत के तीन माह के भीतर यूरोपीय संघ के नागरिकों की स्थिति की सुरक्षा करे। उन्होंने ब्रेग्जिट के समझौते पर संसद में अर्थपूर्ण मतदान कराए जाने के आह्वान को भी 331–286 मतों के अंतर से खारिज कर दिया।

इसका अर्थ यह हुआ कि यूरोपीय संघ (निकासी की अधिसूचना)

विधेयक बिना किसी बदलाव के हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया। इसके बाद यह हाउस ऑफ लॉर्डस में बिना किसी संशोधन के पारित हो गया। वहां इसके पक्ष में 274 और विरोध में 118 मत पड़े। इससे निकासी की शर्तों पर संसद के पास वीटो का अधिकार के मुद्दे पर अब इसे कॉमन्स में दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती। हाउस ऑफ लॉर्डस पहले ही इस बात पर सहमत हो गया था कि यूरोपीय संघ के नागरिकों के दर्जे के मुद्दे गारंटी को विधेयक में दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। इन्हें सांसदों ने खारिज कर दिया था। ऐसी उम्मीद है कि विधेयक को कानून बनाने के लिए अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से शाही मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद एलिजाबेथ लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को इस सप्ताह किसी भी समय सैद्धांतिक तौर पर शुरू कर सकती हैं। हालांकि इस बात के संकेत कम हैं कि वह इस माह के अंत तक बातचीत शुरू कर पाएं। विपक्षी लेबर पार्टी ने पहले मे से अपील की थी कि वह 'वाकई अहम' लॉर्डस संशोधनों को बरकरार रखने पर विचार करें।

मधेसी

नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र को मधेस कहते हैं और यहाँ निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेसी कहते हैं। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहते हैं और तराई में वास करने वाले इन नेपाली लोगों को तराईबासी भी कहते हैं। मधेश शब्द मध्यदेश का अपभ्रंश है। मैथिली, थारु, अवधी, भोजपुरी और अन्य भाषाएँ (जो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बोली जाती है) बोलने वाले लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों जैसे दिखते हैं और जिनकी संस्कृति और रीति–रिवाज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगो जैसी है लेकिन जो नेपाली हैं, वो लोग मधेसी कहलाते हैं।

मधेसी मुल के नेपाली और भारत के बिहारी या उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों में कुछ भी असमानता नहीं है, अन्तर केवल यह है कि मधेसी नेपाली हें जो सीमा के उस पार रहते हैं।

प्राचीन समय में मिथिला और अवध स्वतंत्र राज्यस थें। 17वीं सदी में जब गोर्खा के राजा नेपाल एकीकरण कर रहें थें तब मिथिला और अवध ा के छोटे से भू–भाग पर नेपाल का कब्जा हो गया बाद में अंग्रेजों ने मिथिला और अवध के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और भारत मे गाभा।

भू–विवाद के कारण 1814–16 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नेपाल–अंग्रेज युद्ध हुआ और युद्ध दो वर्षों तक चला अन्त में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधी हुई जिसे सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है। सुगौली संधि के अनुसार नेपाल ने मेची नदी से पुर्व का सारा भू–भाग, घाघरा नदी से पश्चिम का सारा भू–भाग और लगभग सम्पूर्ण तराई भू–भाग अंग्रेजों को सौपना पड़ा। बाद में 1857 में लखनऊ विद्रोह में अंग्रेजों कि मदद करने के एवज में अंग्रेजों ने दक्षिण का सम्पूर्ण तराई भू–भाग नेपाल को वापस लौटा दिया। वापस किये गये इस भू–भाग में मिथिला और अवध के लोग रह रहे थें। यह भू–भाग जब नेपाल में सम्मिलित किया गया तो नेपाल के लोग इस भू–भाग को नया देश या मध्य–देश कहने लगें क्योकि यह भू–भाग नेपाल और भारत के मध्य में था। मध्य–देश का अपभ्रंश मधेश हो गया और मध्य–देशी से मधेशी हो गया।

नेपाल के नए संविधान में मधेसी दोयम दर्जे के नागरिक

संविधान तैयार करना किसी भी देश का अपना अधिकार है और नेपाल ने भी यही किया है। लेकिन क्या नेपाल ने अपने देश की लगभग आधी आबादी यानी मधेसियों को संविधान में पूरा प्रश्रय दिया है? अगर नेपाल के संविधान के कुछ हिस्सों को देखें तो यह साफ हो जाता है कि इसके कई प्रावधान मधेसियों को वहां दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से तराई के मधेसी बहुल हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस वजह से जो हिंसा फैली है उसमें काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है।

जानकारों के मुताबिक नेपाल के पांच विवादित जिलों कांचीपुर, कैइलाली, सुनसरी, झापा और मोरांग को इसके पड़ोसी जिलों में मिलाने का रास्ता तैयार किया गया है। इन पांच जिलों में पहाड़ी लोगों की संख्या ज्यादा है और इन्हें पड़ोस के उन जिलों में मिलाने की तैयारी है जहां मध ोसियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन एकीकरण के बाद इन जिलों में पहाडियों का जनसंख्या अनुपात ज्यादा हो जाएगा। मधेसियों को इस बात का भी गुस्सा है कि किस तरह से संविधान बनाने के लिए गठित अंतरिम समिति की अहम सिफारिशों को खारिज कर दिया गया है। जैसे अंतरिम समिति ने धारा 63 (3) में मधेसियों को उनकी आबादी के हिसाब से संसद में 50 फीसद हिस्सा देने का प्रस्ताव किया गया था। अब उसे हटा दिया गया है। इसी तरह से मधेशियों को सही प्रतिनिधित्व देने संबंधी धारा (21) में भी काफी बदलाव किया गया है।संविधान की धारा 283 में इस बात का साफ तौर पर प्रावधान है कि देश के शीर्ष पदों मसलन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद के अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष आदि के पद पर सिर्फ नेपालवंशी ही स्थापित हो सकते हैं।

इसका साफ मतलब हुआ कि जन्म से नेपाल की नागरिकता लेने वाला या प्राकृतिक तौर पर नागरिक बनने वाले मधेसी इन पदों पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अंतरिम संविधान में हर दस वर्ष पर संसदीय क्षेत्रों का सीमांकन करने की भी भी बात थी जिसे बढ़ा कर 20 ड्डवर्ष कर दिया गया

Develop India Group

है। मधेसियों की मांग है कि इसे 10 वर्ष ही रहने दिया जाए।विदेशी महिलाओं से शादी के बाद उन्हें नागरिकता देने के मामले पर किए गए प्रावधान भी मधेसियों के हितों के खिलाफ है। चूंकि बड़ी संख्या में मधेसियों की शादी अभी भी भारत में होती है और संविधान में नागरिकता के लिए अलग से आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। मधेसियों का कहना है कि शादी होने पर प्राकृतिक तौर पर नेपाल की नागरिकता देने का प्रावधान होना चाहिए।

89वें ऑस्कर अवॉर्ड

सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म 89वां ऑस्कर अवॉर्ड में ***मूनलाइट*** को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला। हालांकि, फंक्शन में तब ड्रामा क्रिएट हो गया, जब बेस्ट फिल्म के लिए गलती से ला ला लैंड का नाम अनाउंस कर दिया गया। बाद में मूनलाइट को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड दिया गया।

14 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई फिल्म ला ला लैंड ने सबसे ज्यादा 6 अवॉर्ड अपने नाम किए। हालांकि, उसे बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड नहीं मिला। प्रेजेंटर वॉरेन बीटी के हाथ में गलत कैटेगरी वाला एनवेलप आ गया, जिससे वो कुछ देर के लिए चुप हो गए। इसी दौरान उनके साथ खड़ी लेडी प्रेजेंटर ने बेस्ट फिल्म के लिए श्ला ला लैंडश का नाम अनाउंस कर दिया। हालांकि, तभी वहां मौजूद एक प्रोड्यूसर ने इसे गलत बताते हुए सही लिफाफा निकाला और मूनलाइट को बेस्ट फिल्म डिक्लेयर किया। बाद में अवॉर्ड के होस्ट जिमी किमेल ने इस पूरे मामले में अपनी गलती मानी।

लॉस एंजिलिस के डॉल्बी थिएटर में हुए इस अवॉर्ड फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड फिल्म मैनचेस्टर बाय द सी के लिए केसी एफ्लेक, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड ला ला लैंड की एक्ट्रेस एमा स्टोन को मिला।

- **वहीं, बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड ला ला लैंड के ही डेमियन शैजेल को मिला।**
- **ब्रिघम टेलर की फिल्म द जंगल बुक ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवॉर्ड अपने नाम किया।**
- **भारतीय मूल के ब्रिटिश कलाकार** देव पटेल **ऑस्कर से चूक गए। उन्हें फिल्म लॉयन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। उनकी जगह महर्शेला अली को फिल्म मूनलाइट के लिए यह अवॉर्ड दिया गया।**
- **बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड फिल्म फेंसेस के लिए विओला डेविस को मिला।**
- **बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवॉर्ड ईरानी डायरेक्टर असगर फरहदी की द सेल्समैन को मिला।**
- **वहीं, 14 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई ला ला लैंड ने बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन में पहला ऑस्कर अवॉर्ड जीता।**
- **फिल्म ला ला लैंड के गाने सिटी ऑफ स्टार्स को मिला ऑरिजिनल सॉन्ग अवॉर्ड।**
- **बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवॉर्ड जूटोपिया को मिला।**
- **व्हाइट हेल्मेट्स को शॉर्ट सब्जेक्ट डॉक्युमेंट्री का ऑस्कर अवॉर्ड मिला।**
- **बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का अवॉर्ड ला ला लैंड को मिला।**
- **बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड पाइपर को दिया गया है।**
- **ऑरिजिनल स्क्रीनप्ले के लिए फिल्म मैनचेस्टर बाई द सी के कीनथ लोनार्गन ने जीता अवॉर्ड।**

हॉलीवुड फिल्म लॉयन में देव पटेल के बचपन का रोल निभाने वाले सनी पवार भी ऑस्कर में पहुंचे। सनी की उम्र महज 8 साल है। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और म्यूजिशियन के प्यार की कहानी है ला ला लैंड की कहानी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और म्यूजिशियन पर बेस्ड है। दोनों एक–दूसरे से मिलते हैं और फिर धीरे–धीरे उन्हें प्यार हो जाता है। फिल्म में एमा स्टोन स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मिया के किरदार में हैं, जो एक कॉफी शॉप में काम करती हैं। वहीं एक्टर रेयान गॉसलिंग म्यूजिशियन सेबस्टियन के रोल में हैं।

गरीब और अश्वेत बच्चे की कहानी है मूनलाइट फिल्म के डायरेक्टर बेरी जेनकिंस हैं। यह एक गरीब और अश्वेत बच्चे के बड़े होने की स्टोरी है। उसे बचपन में कई बार और कई जगहों पर अवॉइड किया जाता है। उसकी मां नशा करती है। बच्चा समलैंगिक यौन–संबंधों को लेकर चल रहे भेदभाव और गरीबी से जूझते हुए बड़ा होता है।ऑस्कर में ओम पुरी को किया गया याद–ऑस्कर सेरेमनी के दौरान दिवंगत बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी को ट्रिब्यूट दिया गया।

दरअसल, सेरेमनी के दौरान एक स्पेशल परफॉर्मेंस के तहत उन स्टार्स को श्रद्धांजलि दी गई, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। चूंकि, ओम पुरी बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के भी स्टार रहे हैं। इसलिए इस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हुआ। ओम पुरी ने हॉलीवुड की ईस्ट इज ईस्ट, गांधी, सिटी ऑफ जॉय और वुल्फ जैसी फिल्मों में काम किया है। ओम पुरी के अलावा, हॉलीवुड के कैरी फिशर, प्रिंस, जेने वाइल्डर, माइकल किमिनो, पैटी ड्यूक, गैरी मार्शल, एंटन येल्चिन, मैरी टैलर मूर, कर्टिस हैनसन और जॉन हर्ट को श्रद्धांजलि दी गई।

ऑस्कर अवॉर्ड में लोग जितना विनर्स को लेकर जानना चाहते थे,

उससे कहीं ज्यादा नजरें सेलिब्रिटीज की ड्रेसेस पर भी थीं। ऑस्कर के रेड कारपेट पर प्रियंका चोपड़ा जहां डिजाइनर राल्फ एंड रूसो के सिल्वर गाउन में नजर आईं, तो वहीं स्लमडॉग मिलियनेयर के एक्टर देव पटेल मां अनीता पटेल के साथ व्हाइट कोट और ब्लैक ट्राउजर में दिखे। उनके अलावा रुथ नेगा, सोफिया कार्सन, ताराजी पी हेनसन, जेसिका बील और जस्टिन टिम्बरलेक और एमा स्टोन जैसे स्टार्स भी नजर आए।

नोबेल पुरस्कार 2017

नोबेल शांति पुरस्कार 2017

इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ***'इंटरनेशनल कैम्पेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स'*** (आईकैन) को दिया गया है. नोबेल कमेटी की प्रमुख बेरिट रेइस–एंडरसन ने कहा कि परमाणु हथियारों पर रोक की संधि की आईकैन की कोशिशों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है. उन्होंने उत्तर कोरिया का जिक्र करते हुए कहा, *''हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है.''* उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न देशों से एटमी हथियार खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील की है.

इंटरनेशनल कैम्पेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स यानी आईकैन सौ से ज्यादा देशों में काम करने गैर सरकारी संस्थाओं का समूह है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। 30 अप्रैल, 2007 को विएना में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया। ***स्वीडन की बीट्रीस फिन्ह इसकी प्रमुख*** हैं।

- **101 देशों के 468 संगठन जुड़े हैं इससे**
- **स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हैं मुख्यालय**
- **भारत के तीन संगठन जुड़े हैं इससे :**

1. **इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलेपमेंट**
2. **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, डिसआर्नामेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन**
3. **पापुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर**

जुलाई में 122 देशों ने परमाणु हथियारों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संधि को मंजूरी दी थी। इसमें अमरीका, रूस, चीन, ब्रिटेन शामिल थे और फ्रांस इस वार्ता से बाहर रहा था।

शांति का नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो दो देशों के बीच भाई–चारे को बढ़ावा देते हैं या फिर समाज के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं जिससे लोगों को नई जिंदगी मिलती है। भारत में ***मदर टेरेसा*** *और* ***कैलाश सत्यार्थी*** *को शांति पुरस्कार दिया जा चुका है जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अहम योगदान दिया। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में जबकि अन्य पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं।*

शांति में नोबेल पुरस्कार : मुख्य तथ्य

- **नोबेल शांति पुरस्कार को पांच व्यक्तियों की एक समिति द्वारा सम्मानित किया जाता है जिन्हें नॉर्वेजियन स्टॉर्टिंग (नॉर्वे की संसद) द्वारा चुना जाता है.**
- **1901–2017 के बीच 98 नोबेल शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.**
- **अब तक 16 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.**
- **1 शांति पुरस्कार विजेता, ले डुक थो, ने नोबेल शांति पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था.**
- **2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले *मलाला यूसुफजई (17) सबसे कम उम्र* के हैं.**

साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017

ब्रिटिश लेखक ***काज़ुओ इशिगूरो*** को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा. उनका सबसे मशहूर उपन्यासों ***'द रिमेन्स ऑफ द डे'*** और ***'नेवर लेट मी गो'*** पर क्रमशः 1993 और 2010 में फिल्में भी बनाई गईं. नोबेल अकादमी ने उनकी प्रशंसा में उनका परिचय इस तरह दिया है, *''जिन्होंने शानदार भावनात्मक उपन्यासों में दुनिया से हमारे संपर्क से जुड़े हमारे भ्रामक अर्थों के नीचे की खाई को उजागर किया है.''* 62 वर्षीय काज़ुओ ने कहा है कि नोबेल पुरस्कार **'सुखद आश्चर्य'** की तरह है.

काज़ुओ इशिगूरो का जन्म जापान के नागासाकी में 1954 में हुआ था. इसी शहर पर 9 साल पहले 1945 में अमरीका ने परमाणु बम गिराया था. बाद में काज़ुओ अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए. उनके पिता को सरे में समुद्र विज्ञानी की नौकरी मिली थी. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केंट से अंग्रेजी और फिलॉसफी की पढ़ाई की. पूर्वी एंगलिया से उन्होंने रचनात्मक लेखन में मास्टर्स किया, जहां मैल्कॉम ब्रैडबरी और एंजेला कार्टर उनके शिक्षक थे. उन्होंने कुल आठ किताबें लिखी हैं, जिनका 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है. उनकी थीसिस ही उनका पहला उपन्यास बनी. 1982 में छपी इस किताब का नाम था *'अ पेल व्यू ऑफ हिल्स'* 1989 में उन्हें ***'द रिमेन्स ऑफ द डे' के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार*** दिया गया. 1995 में उन्हें महारानी की ओर से *'ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर'* का सम्मान दिया गया.

साहित्य में नोबेल पुरस्कार : मुख्य तथ्य

- **साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है.**
- **साहित्य में 1901–2017 के बीच 110 नोबेल पुरस्कारों से**